अध्याय III

कारोबार परिवेश और उभरते बाजार

3.1 भेल के कारोबार परिवेश और उभरते बाजार में बदलाव

2012-17 की अवधि के लिए अपनी नितिगत योजना बनाते हुए, भेल ने यह निर्धारण किया (नवंबर 2011) कि उसके कारोबार परिवेश में एक निश्चित बदलाव आएगा। वित्तीय वर्ष 2010-11 की द्वितीय तिमाही से, वर्तमान और नई परियोजनाओं के लिए कोयले की उपलब्धता में कमी, राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबीज) की खराब वित्तीय स्थिति इत्यादि के कारण निवेश भावनाएं कम हो गई। यह भी स्वीकार किया गया कि पिछले 2010 के अन्त के दशक में भेल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा जैसे (क) जलवायु परिवर्तन (ख) नये उभरते हुए प्रतिस्पर्धी के साथ प्रतिस्पर्धा की तीव्रता में बढ़ोतरी और (ग) संकुचित वितरण अनुसूची।

3.1.1 जलवायु परिवर्तन

बढ़ती पर्यावरणीय समस्याओं के साथ, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने (नवंबर 2003) में 800-1000 मेगावाट के आकार की बड़ी इकाई के सुपरक्रिटिकल मापदंडो के साथ अभिग्रहण की सिफारिश की है जिसे यह देखते हुए कि बड़ी आकार की इकाईयों का अभिग्रहण थर्मल क्षमता संवर्धन की गति को बहुत आवश्यक बढ़ावा देगा और दक्षता में वृद्धि के कारण पर्यावरण पर भी परिणामस्वरूप कम प्रभाव पड़ेगा। उस समय के दौरान, भेल को सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगीकी में अनुभव नहीं था। जलवायु परिवर्तन पर सयुंक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कनवेंशन (यूएनएफसीसीसी) के अन्तर्गत प्रतिबद्धता के अनुसार भारत सरकार ने (जून 2008) जलवायु परिर्वतन पर एक राष्ट्रीय एक्शन प्लान (एनएपीसीसी) को अपनाया जिसमें सौर ऊर्जा के हिस्से को कुल ऊर्जा मिश्रण मे तदनुसार बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन प्रारंभ करने की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत सरकार ने (जनवरी 2010) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) महत्वाकांक्षी लक्ष्य 20000 मेगा-वाट सौर ऊर्जा क्षमता को 2022 तक बढ़ाने के साथ प्रारंभ किया। इस लक्ष्य को बाद में (जून 2015) 100000 मेगा-वाट तक बढाया गया था। भेल की क्षमता सौर ऊर्जा क्षेत्र में बहुत सीमित थी।

3.1.2 प्रतिस्पर्धा में बढोतरी

सुपर-क्रिटिकल प्रौद्योगिकी के साथ उच्च आकार की इकाई को अपनाने के सीईए के निर्णय के परिणामस्वरूप, कई भारतीय कंपनियों ने सुपर-क्रिटीकल प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ देश में ही

विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए संयुक्त उद्यमो[8] (जेवीज़) का गठन किया। इससे भविष्य में अधिक तीव्र प्रतिस्पर्धा के संकेत मिलते थे।

3.1.3 संकुचित वितरण अनुसूची

भेल की एक प्रभाविक 500 मेगावाट की परियोजना के कार्यक्रम को चालू करने की औसत अवधि 47 माह थी जोकि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के मानदंड 42 माह से अधिक थी। हालांकि, अन्य आपूर्तिकर्ता सीईआरसी के निर्धारित मानदंडों को पूरा करने में सक्षम थे। ये आपुर्तिकर्ता पूर्वनिर्मित ढांचों की आपूर्ति द्वारा उत्थापन समय को कम कर सकते थे, जबकि भेल ढांचों की वेल्डिंग का प्रयोग करती थी, जिसमें विलंब सहित गुणवत्ता मुद्दे शामिल थे।

मंत्रालय ने बताया (मई 2017)कि भेल उत्थापन क्षेत्र में आवश्यक सुधार और प्रगतिशील कार्यप्रणाली को अपना रही है। इसने कुछ समय पूर्व 660/800 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल सेटों में बॉल्टेड और पूर्वनिर्मित ढाचे को अपनाया है।

3.2 भेल को सरकार का समर्थन

उसी अवधि में, भारत सरकार ने निम्नलिखित निर्णयों के साथ भेल का समर्थन किया।

(i) भेल सहित स्वदेशी विनिर्माण की सहायता के उद्देश्य से, भारत सरकार ने, सीईए द्वारा, केन्द्रीय/राज्य क्षेत्र की थमर्ल पावर जनरेटिंग कंपनियों द्वारा आमंत्रित की जाने वाली बोलियों में चरणबद्ध स्वदेशी-विनिर्माण सुविधाओं को स्थापित करने की शर्त को शामिल करने के लिए एक परामर्श जारी किया (फरवरी 2010)। यह भेल की प्रतिस्पर्धा को अन्तर्राष्ट्रीय पावर उपकरण विनिर्माणकर्ताओं से जो भारत मे विनिर्माण सुविधाओं को स्थापित करने का इच्छुक नहीं है, को कम करेगा।

(ii) विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने 660 मे.वा. प्रत्येक की 11 इकाई[9] की और 800 मे.वा. प्रत्येक[10] की नौ इकाई की बड़ी निविदा के पालन के लिए मूल्यांकन और अवार्ड संबंधित निर्देशों को (सितम्बर 2009) भेल को निश्चित आदेशों के साथ जारी किया, जबकि यह एल1 नहीं था। इन दोनों बडी निविदाओं में, भेल एल1 नहीं था, लेकिन इन निर्देशों के कारण 6500 मे.वा के भाप जेनरेटर (एसजी) पैकेज और 4240 मेगावाट स्टीम टर्बाइन जेनरेटर (एसटीजी) पैकेज कीमत ₹ 16063.34 करोड़ के आदेश मार्च 2012 और फरवरी 2014 के मध्य प्राप्त कर सका।

(iii) भेल को (फरवरी 2013) 'महारत्न' का दर्जा दिया गया जिससे भेल बोर्ड के नई मदों की खरीद या प्रतिस्थापना के लिए बिना किसी मौद्रिक सीमा के उसके पुंजीगत व्यय की प्रत्यायोजन शक्तियों को बढा दिया; जिससे प्रौद्योगिकी के संयुक्त उद्यमो या रणनीति गठ-जोड़ में प्रवेश करने और

---

[8] *(i) एलएण्डटी-एमएचआई (ii) एलस्टोम भारत फोर्ज (iii) बीजीआर-हिटाची (iv) तोशिबा-जेएसडब्ल्यू, (v) थर्मैक्स-बेग्कॉक एण्ड विलकौक्स और (vi) अंसल्डो-गैम्मन*

[9] *एनटीपीसी/शोलापुर (2 ईकाई), एनटीपीसी/मौंदा (2 ईकाई) मेजा-उर्जा नियम प्राईवेट लिमिटेड (50:50 एनटीपीसी और यूपीआरवीयूएनएल के मध्य) मेजा (2 ईकाई), नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (50:50 एनटीपीसी और बिहार स्टेटपावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड) नबीनगर (3 ईकाई) और डीवीसी/रघुनाथपुर (2 ईकाई)*

[10] *एनटीपीसी/लारा (2 इकाई) एनटीपीसी/-गदरवारा (2 इकाई), एनटीपीसी/दारलीपाली (2 इकाई) और एनटीपीसी/कुडगी (3 इकाई)*

जानकारी के द्वारा, खरीद या अन्य व्यवस्थाओं के द्वारा प्रोद्योगिकी व जानकारी प्राप्त करने वित्तिय संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियो की स्थापना के लिए इक्विटी निवेश करना और भारत या विदेश में विलोपन और अधिग्रहण करने के लिए भेल को अपनी पूंजी उपयोग करने की शक्तियां मिली।

मंत्रालय ने बताया (मई 2017) कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई चरणबद्ध स्वदेशी विनिर्माण सुविधाओ की स्थापना सुपर-क्रिटिकल प्रौद्योगिकी के शीघ्रता से शुरू करते के लिए थी। यद्यपि भेल को बॉयलर और टीजी की दो परियोजनाए बड़ी निविदाओं द्वारा प्राप्त हुए, यह इस स्थिति में नहीं था कि किसी एक परियोजनाओं (रघुनाथपुर परियोजना) को निष्पादित किया जा सके चूंकि परियोजना को 'ऑन हॉल्ड' रखा गया था। इस प्रकार परियोजना ने भेल के टर्नओवर या लाभ में कोई योगदान नहीं दिया। यह भी बताया है कि सभी मुख्य मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएमएज़) ने चाइनीज कंपनियों के अतिरिक्त विनिर्माण सुविधाओं को स्थापित किया और बड़ी निविदाओं के बाद प्रतिस्पर्धा और तीव्र हो गई।

बडी निविदाओं के कारण बढ़ी तीव्र प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए भेल द्वारा आदेशों के प्राप्त करने को आश्वासन ने उसकी सहायता की जबकि वह बोली नहीं जीत पाई। वास्तव में भेल रघुनाथपुर परियोजना से पहले ही ₹ 479 करोड़ के कारोबार को 31 मार्च 2016 तक अंकित कर चुकी थी, जिसके लिए यह एल-1 बोलीदाता नहीं थी।

3.3 भेल पर कारोबार परिवेश परिवर्तन का प्रभाव

3.3.1 कार्यशील परिणामों पर प्रभाव

2011-12 से 2015-16 के दौरान भेल के टर्नओवर के (76.46 प्रतिशत से 80.53 प्रतिशत) का योगदान उर्जा क्षेत्र द्वारा रहा। कंपनी के पास नई/कम परिचालित व्यवसायिक क्षेत्रों के अन्दर प्रभावी विविधता नहीं है। (जैसा कि अध्याय-iv में चर्चा की गई है)। चार्ट-3.1 में 31 मार्च 2016 की समाप्ति पर पांच वर्ष के दौरान भेल के कारोबार और निवल लाभ प्रत्येक वर्ष के आधार पर दर्शाया गया है। भेल ने दोनों टर्नओवर और लाभ प्रदता में तीव्र गिरावट के साथ इसके राजस्व को एकल भाग को और मुड़ते देखा।

चार्ट 3.1 वर्ष-वार टर्नओवर और शुद्ध लाभ

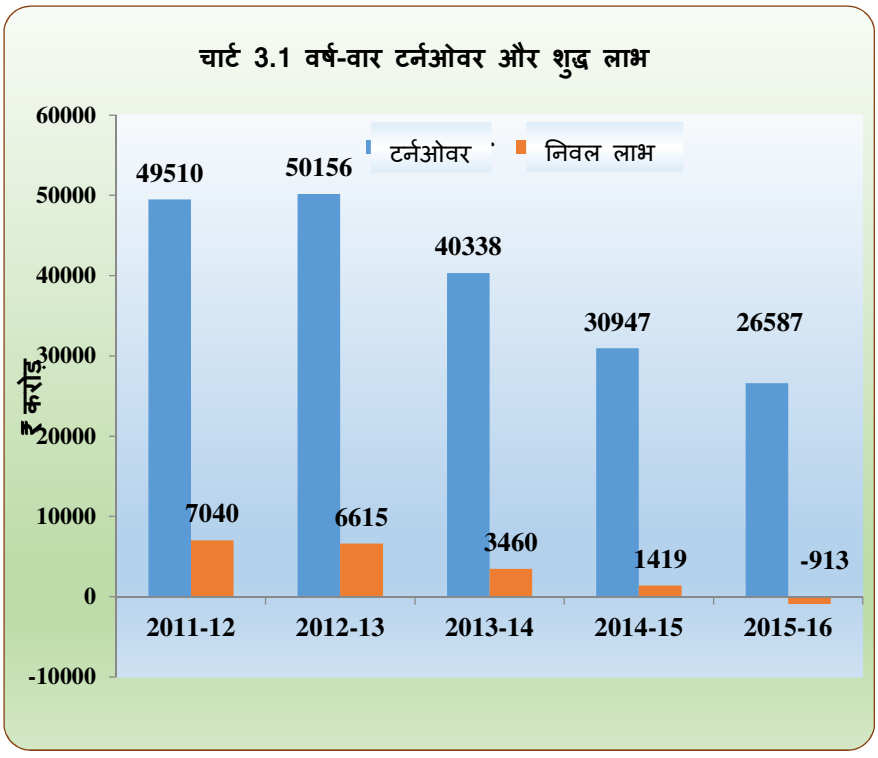

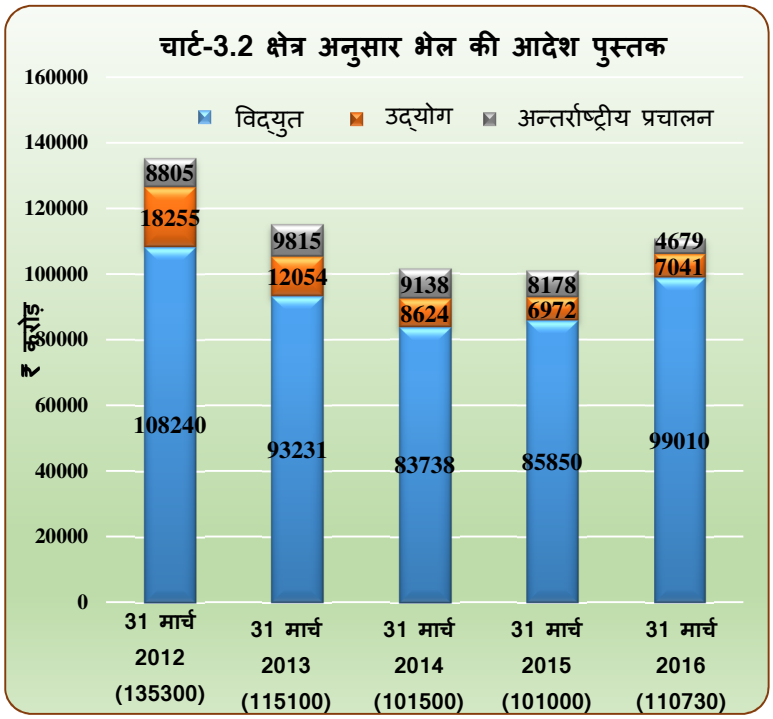

मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि कंपनी के उत्पादों में विविधता लाने के कई प्रयास किये गये थे और ये प्रयास अभी भी जारी थे, जिनसे यह संभावना थी कि आगामी समय में अच्छे परिणाम आएगें।

हालांकि, उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाए कि भेल 2012-17 की प्रस्तावित नीतिगत योजना में संभावित विकास क्षेत्रों अर्थात परिवहन, ट्रांसमिशन और औद्योगिक उत्पादों में नीतिगत दृष्टिकोण[11] को लागू नही कर सका।

3.3.2 आदेश पुस्तिका पर प्रभाव

आदेश पुस्तिका या आदेश संग्रहण, जो उपभोक्ता मांग के स्तर और भविष्य की वित्तीय स्थिरता को इंगित करता है, ₹135300 करोड़ से ₹101000 करोड़ तक मार्च 2012 और मार्च 2015 के मध्य में कम हुआ है। भेल की आदेश पुस्तिका में मार्च 2016 तक सुधार हुआ पर इसमे कुल ₹17950 करोड़ का आदेश शामिल है, जिसके लिए कोई अग्रिम प्राप्त नहीं किया गया है। कंपनी के अपने निर्णय (मार्च 2011) के अनुसार केवल उन आदेशो को लिया गया है, जिनका प्रारंभिक अग्रिम प्राप्त किया जा चुका है। वास्तव में, इस परियोजना के संबंध में प्रारंभिक अग्रिम अब तक (मार्च 2017) पर्यावरण मंजूरी के अभाव में प्राप्त नहीं हुए है। भेल के कुल और कारोबार क्षेत्र वार आदेश 2011-12 से 2015-16 तक साथ के चार्ट में दर्शाया गया है।

2012-13 (37.07 प्रतिशत) और 2015-16 (26.32 प्रतिशत) के मध्य घटता हुआ कारोबार आदेश पुस्तक अनुपात[12] दर्शाता है कि भेल द्वारा प्राप्ति किए गए थे सभी आदेश प्रभावी आदेश नहीं थे। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 31 मार्च 2016 तक ₹110730 करोड़ के आदेश पुस्तक में ₹50645 करोड़ की राशि की 'ऑन होल्ड' परियोजना थी। इस प्रकार लगभग 45.74 प्रतिशत आदेश भेल की आदेश बुक में 31 मार्च 2016 तक अनिष्पादित थे।

---

[11] नीतिगत योजना इलैक्ट्रीक मल्टीपल यूनीट (ईएमयू)/मैनलाईन इलैक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (एमईएमयू) वितरित पावर ट्रेन/हाई स्पीड लोको मेट्रों परियोजना के पूर्वगामी लिखित/सं.उद्यम के लिए जाती है साथ-साथ मिलन और अधिग्रहण परिवहन कारोबार में नाईच प्रौद्योगिकी हेतू सर्कुलेटिंग फ्लूईडाईज़्ड बेड कंबश्चन (सीएफबीसी) बॉयलर के लिए प्रौधोगिकी स्रोत, उन्नत गैस टर्बाइन के साथ उच्च दक्षता में सहयोग, नये उत्पादो के लिए नीतिगत संधि, 400 केवी और 765 केवी के गैस के इंस्यूलेटिड स्वीचयार्ड (डीआरएस) उपकरण इत्यादि का शीघ्रता से विकास का प्रावधान करती है।

[12] वर्ष के आरंभ पर आर्डर बुक के प्रतिशत के अनुसार एक वर्ष के लिए कारोबार

प्रबंधन ने कहा (फरवरी 2017) कि कोयले को आपूर्ति में कमी/कोयला ब्लॉक आवंटन, गैस उपलब्धता में तीव्र कमी, पर्यावरण मंजूरी में विलंब, निधि और यूनिट अधिग्रहण मामलों में विलंब जैसी बाधाओं के कारण औसतन आदेशों को अन्तिम रूप देने के लिए क्षेत्र को अवनति का सामना करना पड़ा। प्रबंधन ने यह भी कहा कि परियोजनाएं अस्थाई प्रकृति होल्ड की थी। मंत्रालय ने इसके अतिरिक्त कहा (मई 2017) कि 'ऑन होल्ड' परियोजनाओं को पुन: चालू करने के प्रयास किये गये थे। एग्जिट कॉन्फ्रेंन्स के पश्चात, प्रबंधन ने बताया (जून 2017) कि भेल ने 'ऑन होल्ड' परियोजनाओं को चालू करने पर ध्यान केन्द्रित किया था और 31 मार्च 2017 तक ₹17411 करोड़ कीमत के अनिष्पादित आदेशों की 9 परियोजनाओं को चालू किया गया। इसके साथ, निष्पादित होने वाले आदेश पुस्तक 31 मार्च 2017 पर ₹65663 करोड़ तक बढ़ गये।

जबकि 'ऑन होल्ड' परियोजनाओं को चालू करने के प्रयासों की सराहना की जाती है, तो यहां यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कम हुए निवेश भावनाओं पर नीतिगत योजना (2012-17) में विचार किया गया जो कि विकास के मार्ग को बनाए रखने के लिए नये व्यापार क्षेत्र में विविधीकरण पर ध्यान केन्द्रित करने के इरादों से था।

3.3.3 देश की संस्थापित क्षमता में भेल के हिस्से पर प्रभाव

चार्ट 3.3 कुल संस्थापित क्षमता की तुलना में भेल द्वारा आपूर्ति किए गए का भाग

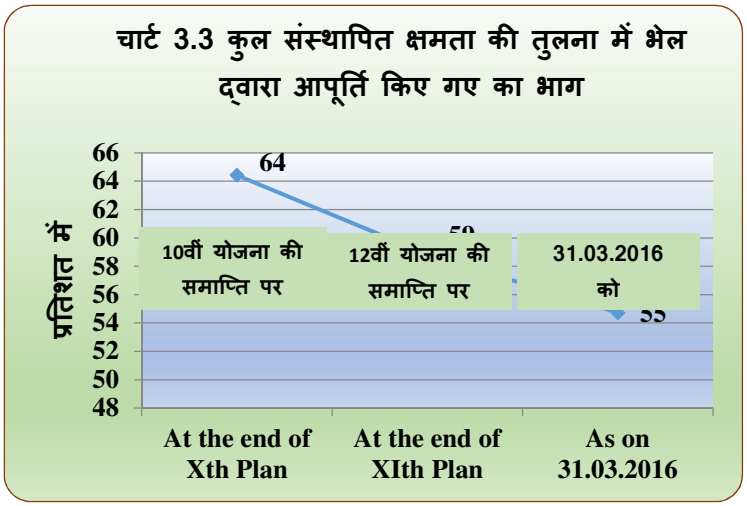

बुनियादी विद्युत क्षेत्र में; भेल अभियांत्रिकी और ड्रम टाईप बॉयलर[13] की आपूर्ति में अग्रणी था। उच्च इकाई आकार/सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी और बढी हुई प्रतिस्पर्धा के साथ (भारतीय कंपनियों जो देश मे ही विनिर्माण सुविधाओं को सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ सहयोग से स्थापित कर रही है) भेल के हिस्से वाले आपूर्ति सेटों में दसवी पंच वर्षीय योजना की समाप्ति के बाद निरन्तर गिरावट देखी गई जैसा की साथ के चार्ट में दिखाया गया है। 31 मार्च 2016, को सुपर क्रिटिकल सेगमेंट में, 33 इकाईयों के प्रति ('ऑन होल्ड' 4 परियोजनाओं के अन्तर्गत 10 इकाईयों सहित) भेल द्वारा कार्यान्वित की गई, 45 इकाईयां इसके प्रतिस्पर्धी द्वारा कार्यान्वित की गई थी जो आगे इसके बुनियादी क्षेत्र में भेल के हिस्से को कम कर सकती थी।

प्रबंधन ने कहा (फरवरी 2017) कि भेल ने इस सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा में उभरने के साथ हालांकि उसने बाजार नेतृत्व को कायम रखा है, तथापि, मौजूदा कंपनी का हिस्सा कम होना स्वाभाविक था। मंत्रालय ने इसमें बताया (मई 2017) कि XII योजना अवधि के दौरान भेल ने 45274 मेगावाट की

[13] *ड्रम बॉयलर को सब क्रिटिकल बॉयलर भी कहा जाता है क्योंकि उन्हें जल के क्रिटिकल प्वाइंट के नीचे यह सुनिश्चित करने के लिए परिचालन करना पडा कि वहां भाप और पानी को अलग करने के मध्य घनत्व का अन्तर था।*

क्षमता अतिरेक्य प्राप्त कर लक्ष्य के 9 प्रतिशत अधिक प्राप्त किया। देश की क्षमता को बढाने वाली भेल सबसे बड़ी एकल सहयोगी बनी रही।

3.3.4 भेल के बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव

अप्रैल 2011 के आरंभ में भेल का बाजार मूल्यांकन ₹97940.71 करोड़ था जो ₹37533.95 करोड़ तक कम हो गया था (16 फरवरी 2017 को) जो 61.68 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है। इसके परिणामस्वरूप भेल में भारत सरकार का बाजार मूल्य भी ₹38092.50 करोड़ कम हो गया। उपरोक्त अवधि के दौरान बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का पूंजीगत वस्तु सूचकांक 13255.14 से 15267.22 तक बढ गया और बीसई पीएसयू सूचक भी उसी स्तर[14] पर रहा, लेकिन भेल के शेयर की कीमत ₹412.17 प्रतिशेयर से ₹153.35 प्रतिशेयर तक शीघ्रता से कम हो गई।

मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि आदेश पुस्तक में पहले से ही 'ऑन होल्ड' विद्युत परियोजनाएं के कारण, और नीतिगत अड़चनों के कारण आदेशों में सुस्ती आने जैसे पर्यावरण मंजूरियां, तेल आपूर्ति अनुबंध, विद्युत खरीद अनुबंध इत्यादि, कोयला आधारित पावर प्लांट, उपकरण विनिर्माताओं पर गंभीर प्रभाव पडा था और इसका असर भेल की शेयर कीमत पर भी पडा।

[14] ***बीएसई पीएसयू सूचकांक अप्रैल 2011 की शुरूआत मे 8960.08 था और 16 फरवरी 2017 को 8461.74 था***